

द सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य

बनाम

मैसूर राज्य और अन्य

(एस. के. दास, जे. एल. कपूर, ए. के. सरकार,

एम. हृदयतुल्ला और रघुबर दयाल, जे. जे.)

बिक्री कर- माल की बिक्री- एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमा पार माल की आवाजाही से जुड़े लेनदेन- कर की देयता- मैसूर बिक्री कर अधिनियम, 1948 (मैसूर 1948 का 46)- भारत का संविधान, अनुच्छेद 286 (2)

दूसरा अपीलकर्ता सीमेंट का निर्माता था और सामग्री के समय भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके एक दर्जन से अधिक कारखाने थे, जिनमें से कोई भी मैसूर राज्य में नहीं था। पहला अपीलकर्ता इसका बिक्री प्रबंधक था और इसका मुख्य कार्यालय बॉम्बे में था और मैसूर राज्य में बैंगलोर में एक शाखा कार्यालय था। सीमेंट एक नियंत्रित वस्तु थी: और सीमेंट खरीदने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरणों से एक मानक रूप में प्राधिकरण प्राप्त करना था जो पहले अपीलकर्ता को उसमें उल्लिखित मात्रा में सीमेंट बेचने के लिए अधिकृत करता था और सीमेंट की आपूर्ति उसमें उल्लिखित कारखाने से की जानी थी। खरीदार को पहले अपीलकर्ता के साथ एक आदेश देना था जिसमें आवश्यकता बताई गई थी कि माल कहाँ भेजा जाना था और उन्हें कैसे भेजा जाना था। वर्तमान मामले में, सभी माल विभिन्न कारखानों से संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ दूसरे अपीलकर्ता को भेजे गए थे, जो सभी प्राधिकरण के बाहर थे। मैसूर राज्य और विभिन्न खरीदारों द्वारा मैसूर राज्य में प्राप्त किए गए, बिक्री कर अधिकारी ने 31 मार्च, 1958 के अपने आदेश द्वारा यह विचार रखा कि यद्यपि

माल में संपत्ति मैसूर राज्य के बाहर के विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को दी गई थी, क्योंकि माल वास्तव में मैसूर राज्य में उपभोग के उद्देश्यों के लिए ऐसी बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मैसूर राज्य में वितरित किया गया था, इसलिए बिक्री उस राज्य में हुई मानी जानी चाहिए और इसलिए, दूसरे अपीलकर्ता के बिक्री प्रबंधक के रूप में पहले अपीलकर्ता द्वारा मैसूर राज्य में ग्राहकों को की गई बिक्री अंतर-राज्य बिक्री के बराबर है और मैसूर बिक्री कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि खरीदारों को वास्तविक वितरण मैसूर राज्य के भीतर था, इसलिए राज्य के बाहर लादे गए और खरीदार को भेजे गए सीमेंट ने बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री में परिवर्तित नहीं किया, बल्कि अंतर-राज्यीय बिक्री थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में हुई बिक्री जिसमें माल की आवाजाही एक संयोजक या अनुबंध की घटना के परिणामस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में हुई थी।

बिक्री, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद, 286 (2) के अंतर्गत आती थी। नतीजतन, ऐसी बिक्री पर बिक्री कर लगाना असंवैधानिक था।

इसके बाद मेसर्स मोहन लाट हरगोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 509 आया।

एंडापुरी नरसिम्हन और पुत्र बनाम उड़ीसा राज्य, [1962] 1 एस. सी. आर. 314, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1955) 28 एस. सी. आर. 603 एम./एस. इताम नारायण एंड संस बनाम सहायक बिक्री आयुक्त ताज, [1955] 2 एस. सी. आर., 483 और पाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बॉम्बे बनाम एस. आर.

सरकार, [1961] 1 एस. सी. आर. 379, पर भरोसा किया।

रोहतास इंडस्ट्रीज लि. बनाम बिहार राज्य, [1961] 12 एस. टी. सी. 615, विशिष्ट।

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णय: दीवानी याचिका सं 255/1961

उच्च न्यायालय, मैसूर के रिट याचिका संख्या 147/1958 में 21 मार्च, 1960 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए आर. जे. कोलाह, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण।

उत्तरदाताओं के लिए सी. के. डाफ्टरी, भारत के सॉलिसिटर- जनरल, बी. आर. एल. अयंगर और पी. डी. मेनन।

28, अगस्त 1962

न्यायालय का निर्णय कपूर, जे. द्वारा दिया गया था।

यह 1958 की रिट याचिका सं. 147 में मैसूर उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ एक अपील है जिसमें अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया गया है और 1 अप्रैल, 1955 से 31 मार्च, 1956 तक की मूल्यांकन अवधि के लिए मूल्यांकन के आदेश को रद्द करने के लिए संविधान की धारा 227 वैलिडेटिंग एक्ट (1956 का VIII) के कारण इस अपील में अपीलकर्ताओं ने 1, अप्रैल 1955 से 6 सितंबर, 1955 तक की अवधि के लिए अपने दायित्व को चुनौती नहीं दी।

इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य ये हैं: अपीलकर्ता नं. 1- सीमेंट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड- 21 अप्रैल, 1954 के एक समझौते के तहत नियुक्त दूसरे अपीलकर्ता- द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड के बिक्री प्रबंधक हैं। उच्च न्यायालय

ने पहले अपीलकर्ता को दूसरे अपीलकर्ता का वितरक बताया है। दूसरा अपीलकर्ता सीमेंट का निर्माता है और सामग्री के समय भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके एक दर्जन से अधिक कारखाने थे, जिनमें से कोई भी मैसूर राज्य में नहीं था। प्रथम अपीलकर्ता का मुख्य कार्यालय बॉम्बे में है और तब मैसूर राज्य में बेंगलोर में इसका एक शाखा कार्यालय था। पहले अपीलकर्ता को मैसूर बिक्री कर अधिनियम 1948 के तहत एक विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसे इसके बाद 'मैसूर अधिनियम' कहा जाता है। सभी भौतिक समय में सीमेंट एक नियंत्रित वस्तु थी और अभी भी है। चाहे बिक्री किसी सरकारी विभाग, अर्थात् आपूर्ति और निपटान महानिदेशक, भारत सरकार, नई दिल्ली, या उक्त अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति या जनता को की गई हो, यह उचित सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीदारों को दिए गए प्राधिकरणों पर प्रभावी थी और उनके द्वारा पहले अपीलकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। जनता और सरकार दोनों द्वारा खरीद के संबंध में कार्यप्रणाली कमोबेश समान थी। यह इस प्रकार था: सीमेंट खरीदने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को एक मानक रूप में प्राधिकरण प्राप्त करना था जो पहले अपीलकर्ता को उसमें उल्लिखित मात्रा में सीमेंट बेचने के लिए अधिकृत करता था और सीमेंट की आपूर्ति उसमें उल्लिखित कारखाने से की जानी थी। वह दस्तावेज़ निम्नलिखित रूप में था जो वास्तव में एक सरकारी ठेकेदार को बिक्री से संबंधित है।

“भारत सरकार- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

क्षेत्रीय मानद सीमेंट का कार्यालय

सलाहकार 4/12 रेस कोर्स रोड, कोयंबटूर।

केंद्रीय कोटा।

प्राधिकरण सं. आरए/सीटी/28/सीएमआई/172 सीक्यू

दिनांकित 8-10-1955

(सी. एन. टी. ई. एल. ई. सी.)

अवधि IV/55, आपूर्तिकर्ताओं के नामद सीमेंट मार्केटिंग, कं. ऑफ इंडिया, पी. बॉक्स नंबर 613, शुगर कंपनी बिल्डिंग बेंगलोर- 2

आप इस प्राधिकरण के तहत नीचे उल्लिखित मात्रा में सीमेंट बेचने के लिए अधिकृत हैं। बिक्री आपके और खरीदार के बीच एक सीधा सौदा होगा। सरकार किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है:-

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके पक्ष में प्राधिकरण जारी किया गया है-1. मेसर्स जी. एस. दुग्गल एंड कंपनी लि. इंजीनियर और ठेकेदार, जलहल्ली पी. ओ., बेंगलोर

सीमेंट की आपूर्ति के लिए आवश्यक सीमेंट कारखाने या कंपनी का नाम- 2. मुधुक्कराई शाहाबाद

मात्रा- 3. 300 टन

आर. एल. का नाम, किस स्टेशन पर सीमेंट बुक किया जाना है- 4. बेंगलोर

टिप्पणी-

संदर्भ सं., उपरोक्त इंडेंटों से जे/117/115 तिथि 29-9-55 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए टाइलों के निर्माण के लिए। कमांडर वर्क्स इंजीनियर्स (बी ई एल पी), जालाहल्ली द्वारा अनुशंसित आपूर्ति।

किस उद्देश्य के लिए और किस स्थान पर वास्तव में सीमेंट की खपत की जाएगी, इसका पूरा विवरण; प्राथमिकता, रक्षा कार्य।

एस. डी. सी. सी. रामनाथ,

रेग, माननीय सीमेंट सलाहकार

(कोइम्बटूर)

एल में प्रतिलिपि बनाएँ, इन्डेन्टर।

2. दि. विकास अधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विकास शाखा, (रसायन, खनिज उद्योग) शाहजहां रोड, नई दिल्ली।

3. जानकारी के लिए मैसूर बेंगलोर में नागरिक आपूर्ति नियंत्रक "

यह प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन था: इसका उपयोग 15 दिनों के भीतर किया जाना था; जारी किए गए सीमेंट का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता था जिसके लिए इसे दिया गया था; प्राधिकरण हस्तांतरणीय नहीं था; जारी करने वाला प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी समय प्राधिकरण को रद्द कर सकता था और यहां तक कि प्राधिकरण के तहत बुक किए गए आदेशों को भी रद्द किया जा सकता था, खरीदार या इंडेंटर को तब दूसरे अपीलकर्ता के बिक्री प्रबंधकों के रूप में पहले अपीलकर्ता के साथ एक आदेश देना था, जिसमें आवश्यकता बताई गई थी कि माल कहां भेजा जाना था और उन्हें कैसे भेजा जाना था। विक्रेता ने पहले अपीलकर्ता के साथ एक अनुबंध किया। यह अनुबंध एक मानक रूप में है और बिक्री की शर्तें देता है। इसके बाद पहले अपीलकर्ता ने अपने बॉम्बे कार्यालय को खरीदार के निर्देशों और प्राधिकरण के अनुसार सीमेंट भेजने का निर्देश दिया। इस पत्र में उन्हें प्राधिकरण की संख्या और उस व्यक्ति का उल्लेख करना था जिसने इसे जारी किया था और यह भी उल्लेख करना था कि सामान किसे भेजा जाना था और कैसे और कुछ अन्य विवरण जो इस अपील के उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं हैं, भी दिए जाने थे।

प्रत्येक निर्देश इंगित करता है कि यह अपीलकर्ता संख्या 2 के लिए और उसकी ओर से अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा उसके बिक्री प्रबंधकों के रूप में जारी किया गया था।

निर्देश पत्र की एक प्रति उस कारखाने को भेजी गई थी जहाँ से माल भेजा जाना था और प्राधिकरण का विवरण उसमें उल्लेख किया जाना था, इसके बाद पहले अपीलकर्ता ने एक सलाह भेजी माल के लिए रेलवे रसीद संलग्न करने वाले खरीदार और इस सलाह में उस प्राधिकरण के विवरण का भी उल्लेख किया गया है जिसके खिलाफ माल भेजा जा रहा था। बिक्री अनुबंध और उपरोक्त सलाह दोनों में कहा गया है कि जब से कारखाने द्वारा वाहक को डिलीवरी की गई थी और माल के लिए रेलवे रसीद प्राप्त की गई थी, तब से माल खरीदार के जोखिम पर भेजा जा रहा था। वर्तमान मामले में सभी माल दूसरे अपीलकर्ता से संबंधित विभिन्न कारखानों से प्राधिकरणों के खिलाफ भेजे गए थे, जो प्रासंगिक समय पर मैसूर राज्य के बाहर स्थित थे और विभिन्न खरीदारों द्वारा मैसूर राज्य में प्राप्त किए गए थे।

प्रथम अपीलकर्ता की स्थिति वैसी ही है जैसी बिक्री कर अधिकारी ने 31 मार्च, 1958 के अपने आदेश में स्वीकार की थी, दूसरी अपीलकर्ता के बिक्री प्रबंधकों की स्थिति, लेकिन लेनदेन की प्रकृति के संबंध में बिक्री कर अधिकारी ने पाया कि:-

“यद्यपि माल में संपत्ति राज्य के बाहर के विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को तुरंत दी जाती है, माल को राज्य के बाहर के वाहकों को सौंप दिया जाता है और रेलवे रसीद निकाल ली जाती है क्योंकि माल वास्तव में राज्य में उपभोग के उद्देश्यों के लिए ऐसी बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वितरित किया गया है, बिक्री मैसूर राज्य में हुई मानी जाती है।”

और उन्होंने फिर कहा:-

“इस प्रकार मैसूर राज्य के बाहर स्थित ए. सी. सी. कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट की बिक्री विक्रेता मेसर्स सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ

इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। बेंगलोर, मैसूर राज्य में विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए अंतर- राज्य बिक्री के बराबर हैं और इसलिए मैसूर बिक्री कर अधिनियम 48 के लिए उत्तरदायी है।"

अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि पहले अपीलकर्ता का मैसूर राज्य के भीतर बेंगलोर में एक शाखा कार्यालय था और जनता ने उन्हें दिए गए परमिट के खिलाफ सीमेंट की आपूर्ति के लिए पहले अपीलकर्ता के साथ अपने आदेश रखे; कि पहला अपीलकर्ता, जिसने सीमेंट की आपूर्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, इच्छुक खरीदारों से कीमत एकत्र की और फिर दूसरे अपीलकर्ता के कारखानों में से एक को खरीदारों को सीमेंट की आपूर्ति करने का निर्देश दिया और खरीदार को वास्तविक डिलीवरी मैसूर राज्य के भीतर थी और इसलिए यह तर्क कि सीमेंट को मैसूर राज्य के बाहर लोड किया गया था और खरीदार को भेजा गया था, बिक्री को अंतर- राज्यीय बिक्री में परिवर्तित नहीं करता था, बल्कि अंतर-राज्यीय बिक्री थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लेन- देन की वास्तविक प्रकृति पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया था।

ऊपर उल्लिखित कार्यप्रणाली से पता चलता है कि एक इच्छुक खरीदार को सीमेंट प्राप्त करने से पहले उसे एक सरकारी प्राधिकरण से प्राधिकरण प्राप्त करना पड़ता था जो उस कारखाने को नामित करता था जिससे इच्छुक खरीदार को सीमेंट की आपूर्ति प्राप्त करनी होती थी। आदेश के साथ उस प्राधिकरण को पहले अपीलकर्ता को देना पड़ता था और मानक रूप में अनुबंध दर्ज होने के बाद पहले अपीलकर्ता ने प्राधिकरण में नामित कारखाने को आदेश भेजा और उस कारखाने ने फिर खरीदार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की। जिस कारखाने से सीमेंट की आपूर्ति की जानी थी, वह हाथ में या पहले अपीलकर्ता के विकल्प पर नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सरकारी प्राधिकरण को तय करना था, ताकि सीमेंट की आपूर्ति किसी विशेष कारखाने से की



जाए।

पहली अपीलकर्ता की पसंद पर नहीं बल्कि प्राधिकरण के अनुसार आपूर्ति की गई।

यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में जो बिक्री हुई थी, जिसमें किसी वाचा या बिक्री अनुबंध की घटना के परिणामस्वरूप माल की आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में हुई थी, वह संविधान के अनुच्छेद 286 (2) के अंतर्गत आती है और इसलिए ऐसी बिक्री पर बिक्री कर लगाना असंवैधानिक था। संबंधित समय पर लागू अनुच्छेद, अर्थात् इसके संशोधन से पहले, इस प्रकार थाः—

“286 (1) “राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने को लागू या अधिकृत नहीं करेगा जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है।

(क) राज्य के बाहर; या

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या निर्यात के दौरान।

स्पष्टीकरण। .....

(2) जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उसके सिवाय किसी राज्य की कोई विधि किसी माल की बिक्री या खरीद पर कर अधिरोपित या अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, जहां ऐसी बिक्री या खरीद अंतर- राज्य या वाणिज्य के दौरान होती है:

प्रदान किया गया। ”

तब से इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था और संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम द्वारा इसके स्थान पर एक और प्रतिस्थापित किया गया था,

लेकिन विचाराधीन बिक्री संशोधन से पहले थी।

वर्तमान मामले में अनुबंध में ही कारखाने से खरीदार तक माल की आवाजाही शामिल थी। सीमा पार एक राज्य से दूसरे राज्य में क्योंकि कारखाने मैसूर राज्य के बाहर थे और इसलिए लेनदेन स्पष्ट रूप से अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री का लेनदेन था। लेन-देन की प्रकृति और सीमेंट की बिक्री या खरीद के लिए आवश्यक प्रारंभिक स्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि बिक्री के कारण ही एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही नहीं होती थी। वर्तमान मामले में साबित किए गए अनुबंधों की आवश्यक विशेषताएं मैसर्स मोहन लाल हरगोविंद, मध्य प्रदेश राज्य के अनुरूप हैं। उस मामले में निर्धारिती मध्य प्रदेश में बिरयानी बनाने और बेचने का व्यवसाय करने वाली एक फर्म थी। अपने व्यवसाय के दौरान उन्होंने बॉम्बे राज्य के विक्रेताओं से तैयार तंबाकू का आयात किया, इसे बिटियों में लुढकाया और विभिन्न अन्य राज्यों को बिरयानी का निर्यात किया। बॉम्बे राज्य से तंबाकू के दोनों निर्यातक जो निर्धारिती और निर्धारिती की आपूर्ति करते थे, वे पी. एंड बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947 के तहत पंजीकृत विक्रेता थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती उन व्यक्तियों से तैयार तंबाकू का मध्य प्रदेश में आयात करते थे जो बॉम्बे राज्य में तंबाकू के प्रसंस्करण और माल की बिक्री का व्यवसाय चल रहा था और इन लेन-देनों के परिणामस्वरूप बॉम्बे राज्य से मध्य प्रदेश राज्य में माल की आवाजाही हुई और इसलिए लेनदेन में राज्य की सीमा के पार माल की आवाजाही शामिल थी और वे संविधान के अनुच्छेद 286 (2) के आधार पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे। द स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचीन एंड अदर्स बनाम द बॉम्बे को. लिड.) में, जो कि आर्ट, 286 (1) (बी) यानी निर्यात व्यापार के दौरान बिक्री और खरीद के तहत एक मामला था, पतंजलि शास्त्री, सी. जे. ने कहा:—

“इस प्रकार निर्यात द्वारा बिक्री में एकीकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला

शामिल होती है जो एक विदेशी खरीदार के साथ बिक्री के समझौते से शुरू होती है और भूमि या समुद्र के माध्यम से देश से बाहर परिवहन के लिए एक सामान्य वाहक को माल की डिलीवरी के साथ समाप्त होती है। ऐसी बिक्री को उस निर्यात से अलग नहीं किया जा सकता है जिसके बिना इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है, और एकल लेनदेन के कुछ हिस्सों से बिक्री और परिणामी निर्यात को अलग नहीं किया जा सकता है।"

पी.1120 विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने फिर कहा:

"तदनुसार हम मानते हैं कि जो कुछ भी अनुच्छेद 286 (1) की बिक्री और खरीद के अंतर्गत आता है या नहीं भी आता है, जो स्वयं भारत के क्षेत्र से या क्षेत्र में माल के निर्यात या आयात का कारण बनता है, वह छूट के दायरे में आता है और यह इन अपीलों के निपटारे के लिए पर्याप्त है।"

इस प्रकार अनुच्छेद 286 (1) (बी) के अंतर्गत आने वाली बिक्री एक ऐसी बिक्री होनी चाहिए जो निर्यात का अवसर हो। फिर से त्रावणकोर कोचीन और ओथेरे वी. वी. राज्य में शम्मुघा विलास काजू कारखाना और अन्य "इन द कोर्स" शब्दों की व्याख्या न केवल देश से बाहर माल के निर्यात के अंत तक निर्देशित गतिविधियों के दौरान होने वाली बिक्री के रूप में की गई थी, बल्कि ऐसी गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में या उनसे जुड़ी हुई थी। पी. 63 विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने 'एकीकृत गतिविधियाँ' शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की:-

"एकीकृत गतिविधियाँ" वाक्यांश का उपयोग पिछले निर्णय में यह दर्शाने के लिए किया गया था कि "ऐसी बिक्री" (यानी एक बिक्री जो निर्यात का अवसर देती है)

को निर्यात से अलग नहीं किया जा सकता है जिसके बिना इसे प्रभावित नहीं किया जा सकता है, और बिक्री और परिणामी निर्यात एक ही लेनदेन के हिस्से हैं। यह इस मायने में है कि दो गतिविधियों- बिक्री और निर्यात- को एकीकृत कहा गया था।

एंडुपुरी नरसिम्हम और सोनव में उड़ीसा राज्य, अनुच्छेद 286 (1) (ख) द्वारा कवर की गई बिक्री के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल उन वस्तुओं की बिक्री या खरीद जो भारत के क्षेत्र से बाहर या क्षेत्र में माल के निर्यात या आयात का कारण बनती हैं, वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर आदेश लगाने से मुक्त थी और अंतर-राज्यीय बिक्री पर आदेश लगाने के खिलाफ निषेध के संबंध में यह कहा गया था कि परीक्षण यह था कि खरीद अंतर-राज्यीय हो सकती है, यह आवश्यक है कि बिक्री या खरीद के अनुबंध के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का परिवहन होना चाहिए। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य की निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्ताव के समर्थन में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था:-

बिक्री को अंतर-राज्यीय व्यापार के क्रम में तभी कहा जा सकता है जब दो शर्तें सहमत हों: (1) वस्तुओं की बिक्री, और (2) बिक्री अनुबंध के तहत उन वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन। जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान कोई बिक्री नहीं हो सकती है।

इस प्रकार अंतर-राज्यीय बिक्री के भीतर बिक्री लाने के लिए जो परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, वे यह हैं कि लेनदेन में सीमा पार माल की आवाजाही शामिल होनी चाहिए (मोहनलाल हरगोविंद का मामला; लेनदेन अंतर-राज्य हैं जिसमें ऐसी बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में माल वास्तव में दूसरे राज्य में उपभोग के लिए वितरित किया जाता है; मेसर्स राम नारायण एंड संस बनाम बिक्री कर के सहायक आयुक्त, बिक्री के अनुबंध में बिक्री के अनुबंध के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में

माल का परिवहन शामिल होना चाहिए; बंगाल इम्युनिटी कंपनी का मामला, निर्यात या आयात के दौरान बिक्री के मामले में निर्धारित परीक्षण एकीकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला थी जो बिक्री के समझौते से शुरू होती थी और भूमि या समुद्र द्वारा निर्यात के लिए एक आम वाहक को माल की डिलीवरी के साथ समाप्त होती थी; बॉम्बे कंपनी लिमिटेड, मामला के दौरान न केवल निर्देशित गतिविधियों के दौरान होने वाली बिक्री का अर्थ समझाया गया था। देश से बाहर माल के निर्यात के अंत तक, लेकिन ऐसी गतिविधियों के हिस्से के रूप में या उनसे जुड़ी हुई और 'एकीकृत गतिविधियों' को समान भाषा में समझाया गया था। इस न्यायालय ने हंडुपर्ट नरसिम्हम के मामले में इन परीक्षणों को फिर से स्वीकार कर लिया। इंस. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74) के 3, विधानमंडल ने मोहन लाल हरगोविंद के मामले में निर्धारित अंतर-राज्यीय बिक्री को नियंत्रित करने वाले प्रमुख को स्वीकार कर लिया है। राज्य के बाहर अंतर-राज्यीय बिक्री या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री या खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत हैं:

“8.3 माल की बिक्री या खरीद इस अवधि के बीच में हुई मानी

जाएगी- राज्य व्यापार या वाणिज्य यदि बिक्री या खरीद-

(क) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का अवसर; या

(ख) माल की आवाजाही के दौरान स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में।”

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लिड, बॉम्बे बनाम एस. आर. सरकार और एक अन्य (4) शाह, जे. में, यह समझाते हुए कि कौन सी बिक्री सी. एल. द्वारा कवर की जाती है। (क) ऊपर 8.3 में कहा गया है:

“धारा का क्ल. (ए) 3 खंड (ख) में शामिल बिक्री के अलावा अन्य बिक्री शामिल है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही बिक्री के अनुबंध के संयोजक या घटना का परिणाम है, और माल में संपत्ति किसी भी राज्य में गुजरती है।”

जैसा कि वर्तमान मामले में बिक्री अनुबंधों के तहत ऊपर कहा गया है कि मैसूर राज्य के बाहर से मैसूर राज्य में माल का परिवहन होता था और लेनदेन में सीमा पार माल की आवाजाही शामिल थी। इस प्रकार यदि माल बिक्री अनुबंध के तहत स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वे राज्य के भीतर की बिक्री थी। यह पहले अपीलकर्ता की इच्छा नहीं थी कि वह दूसरे अपीलकर्ता के किसी भी कारखाने से खरीदार को माल की आपूर्ति करे। कारखानों को सरकार द्वारा प्राधिकरणों द्वारा नामित किया गया था जो खरीदार और विक्रेता के बीच अनुबंध का आधार थे। वर्तमान मामले के तथ्यों पर इन परीक्षणों को लागू करते हुए हमारी राय है कि बिक्री अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति में थी और बिक्री कर से मुक्त थी। इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले में बिक्री के अनुबंधों को गलती से राज्य के भीतर की बिक्री माना गया है।

रोहियास इंडस्ट्रीज लि. बनाम बिहार राज्य में निर्णय: जिसके लिए प्रत्यर्थी द्वारा संदर्भ दिया गया था, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि पहले अपीलकर्ता और दूसरे अपीलकर्ता के बीच समझौता रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उपरोक्त मामले में सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया के बीच मौजूद समझौते से अलग है। उन दोनों कंपनियों के बीच समझौते की जांच करने पर इस अदालत ने कहा कि दोनों के बीच जो संबंध था वह विक्रेता और खरीदार का था, न कि प्रमुख एजेंट का। वर्तमान मामले में समझौता काफी अलग है। 21 अप्रैल, 1954 को दोनों अपीलार्थियों और पटियाला सीमेंट कंपनी के बीच हुए समझौते के पहले खंड में, पहले अपीलकर्ता को

दूसरे अपीलकर्ता का एकमात्र और अनन्य बिक्री प्रबंधक नियुक्त किया गया था और इस तरह पहला अपीलकर्ता इसमें प्रवेश करने का हकदार था।

बिक्री के अनुबंध, उसी का भुगतान प्राप्त करते हैं और प्रधानाचार्यों की ओर से किए गए बिक्री के अनुबंधों के संबंध में प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी कार्य और चीजें करते हैं, बिक्री मूल्य और बिक्री के नियम और शर्तें प्रधानाचार्यों द्वारा निर्धारित की जानी थीं। बिक्री प्रबंधक को अपने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों को भारत में ऐसे स्थानों पर रखना था जो प्राचार्यों द्वारा निर्धारित किए गए थे। बिक्री प्रबंधकों के सभी स्थापना शुल्क और अन्य खर्च उनकी ओर से थे।

प्रधानाचार्यों द्वारा उनकी वार्षिक बिक्री के अनुपात में भुगतान किया जाना था। हर महीने के अंत में बिक्री प्रबंधकों को प्रत्येक प्राचार्य की ओर से अपने द्वारा बिक्री अनुबंध दिखाने वाले प्राचार्यों के खातों में जमा करना होता था, 31 जुलाई को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, बिक्री प्रबंधकों को वर्ष के दौरान अपने सभी कार्यों का उचित लेखा-जोखा बनाना होता था और उन्हें प्राचार्यों को पुष्टि के लिए जमा करने के बाद प्रत्येक प्राचार्य को वार्षिक बिक्री हस्तांतरण की कीमत का भुगतान करना पड़ता था, जिनसे वे संबंधित थे। खंड 10 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानाचार्यों के निर्देशों के अधीन बिक्री प्रबंधकों को सीमेंट के त्वरित और आर्थिक परिवहन को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी थीं। ये शब्द रोहतास इंडस्ट्रीज लिड के मामले से काफी अलग हैं। और इसलिए उस निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 1955 से 6 सितंबर, 1955 की अवधि को छोड़कर निर्धारण वर्ष के लिए अपीलकर्ता पर बिक्री कर का अधिरोपण अवैध था और उस अवधि के लिए देय नहीं था। इसलिए अपील को उस हद तक अनुमति दी जाती है और

अपीलकर्ताओं की याचिका सफल हो जाती है लेकिन यह उपरोक्त अवधि के लिए भुगतान किए गए कर को प्रभावित नहीं करेगी। अपीलार्थियों की आंशिक सफलता को देखते हुए वे अपील की आधी लागत के हकदार होंगे।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति है।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।